भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

18.03.2026 के

अतारांकित प्रश्न सं. 4365 का उत्तर

चित्तौड़गढ़/प्रतापगढ़/उदयपुर में नई रेलवे लाइनें

4365. श्री चन्द्र प्रकाश जोशी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान के चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और उदयपुर जिलों में नई रेलवे लाइनें बिछाने के लिए कोई सर्वेक्षण कार्य पूरा किया गया है या वर्तमान में कोई प्रस्ताव अनुमोदन के लिए विचाराधीन है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त जिलों में चल रही रेलवे परियोजनाओं (नई लाइन, दोहरीकरण) की अनुमानित लागत का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है और उनकी प्रगति/स्थिति सहित अब तक कितनी राशि खर्च की गई है;

(ग) सर्वेक्षण पूरा होने के बाद नई रेलवे लाइनों और दोहरीकरण परियोजनाओं की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति की स्थिति क्या है;

(घ) क्या सरकार उक्त जिलों में रेल संपर्क को मजबूत करने के लिए किसी विशेष प्राथमिकता योजना पर काम कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त परियोजनाओं के पूरा होने के बाद क्षेत्रीय आर्थिक विकास, पर्यटन, औद्योगिक गतिविधियों और रोजगार सृजन पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ): राजस्थान के चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और उदयपुर जिलों में कनेक्टिविटी सुधारने के लिए, निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए अंतिम स्थान सर्वेक्षण को स्वीकृति दी गई है:

i. **नीमच -सिंगोली -बेंगू-रावत भाटा-कोटा नई लाइन (201 कि.मी.)**
ii. **मंदसौर-प्रतापगढ़-घाटोल-बांसवाड़ा नई लाइन (120 कि.मी.)**
iii. **नीमच-बांसवाड़ा-दाहोद-अलीराजपुर-नंदुरबार नई लाइन (380 कि.मी.)**

iv. चित्तौड़गढ़-मावली-देबारी दोहरीकरण (99 कि.मी.)

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के पश्चात्, परियोजना को स्वीकृति देने के लिए राज्य सरकारों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श और आवश्यक अनुमोदन यथा नीति आयोग, वित्त मंत्रालय आदि के मूल्यांकन अपेक्षित होता है। चूंकि परियोजनाओं को स्वीकृत करना एक सतत और गतिशील प्रक्रिया है, इसलिए निश्चित समय-सीमा का निर्धारण विभिन्न हितधारकों के मूल्यांकन और अनुमोदन के आधार पर किया जाता है।

इसके अलावा, राजस्थान के चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और उदयपुर जिलों में संपर्कता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित परियोजनाओं के कार्य शुरू किए गए हैं :

(1) नीमच-बड़ी सदरी नई लाइन (48 कि.मी.): ₹495 करोड़ की लागत पर कार्य को स्वीकृत किया गया है। कार्य की स्थिति निम्नानुसार है:

कार्य	स्थिति
भूमि अधिग्रहण	पूरा हो गया है।
बड़े पुल	7 में से 4 बड़े पुलों का कार्य पूरा हो गया है और शेष पुलों का कार्य शुरू किया गया है।
आरयूबी	30 में से 9 आरयूबी का कार्य पूरा हो गया है और शेष आरयूबी का कार्य शुरू किया गया है।
स्टेशन भवन	6 में से 2 स्टेशन भवनों का कार्य पूरा हो गया है और शेष स्टेशन भवनों का कार्य शुरू किया गया है।

(2) मावली-देवगढ़ देवगढ़ मदारिया अमान परिवर्तन (83 कि.मी.): ₹969 करोड़ की लागत पर कार्य को स्वीकृत किया गया है। कार्य की स्थिति निम्नानुसार है:

कार्य	स्थिति
भूमि अधिग्रहण	पूरा हो गया है।
बड़े पुल	10 में से 6 बड़े पुलों का कार्य पूरा हो गया है और शेष पुलों का कार्य शुरू किया गया है।
आरयूबी	64 में से 38 आरयूबी का कार्य पूरा हो गया है और शेष आरयूबी का

	कार्य शुरू किया गया है।
स्टेशन भवन	7 में से 4 स्टेशन भवनों का कार्य पूरा हो गया है और शेष स्टेशन भवनों का कार्य शुरू किया गया है।

(3) अज़मेर-चन्देरिया दोहरीकरण (178 कि.मी.): कार्य को ₹1635 करोड़ की लागत पर स्वीकृत किया गया है। कार्य की स्थिति निम्नानुसार है:

कार्य	स्थिति
भूमि अधिग्रहण	114 हेक्ट. में से 75 हेक्ट. का अधिग्रहण किया गया है और शेष भूमि के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य शुरू किया गया है।
बड़े पुल	16 बड़े पुलों का कार्य शुरू किया गया है।
आरयूबी	31 आरयूबी का कार्य शुरू किया गया है।
स्टेशन भवन	13 में से 1 स्टेशन भवनों का कार्य पूरा हो गया है और शेष स्टेशन भवनों का कार्य शुरू किया गया है।

(4) उमरा-उदयपुर-देबरी दोहरीकरण (25 कि.मी.):

इस परियोजना को दिसम्बर-2025 में ₹492 करोड़ की लागत पर स्वीकृत किया गया है। इस परियोजना को 'विशेष रेल परियोजना' के रूप में घोषित किया गया है और भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकरण भी नियुक्त किया गया है। भूमि अधिग्रहण का कार्य आरंभ किया गया है।

<u>राजस्थान</u>

रेल बजटः

हाल के वर्षों में बजट आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। राजस्थान राज्य में पूर्णतः/अंशतः आने वाली अवसंरचना परियोजनाओं और संरक्षा कार्यों के लिए बजट आबंटन निम्नानुसार है:

अवधि	परिव्यय
2009-14	682 करोड़ रु. प्रति वर्ष
2025-26	9,960 करोड़ रु. (लगभग 15 गुना)

रेलपथ निर्माणः

वर्ष 2009-14 और 2014-25 के दौरान राजस्थान राज्य में पूर्णत:/अंशत: आने वाले नए रेलपथो के निर्माण का ब्यौरा निम्नानुसार है:

अवधि	कमीशन किए गए गए रेलपथ	नए रेलपथ की औसत कमीशनिंग
2009-14	798 कि.मी.	159.60 कि.मी. प्रति वर्ष
2014-25	3,815 कि.मी.	346.82 कि.मी. प्रति वर्ष (2 गुना से अधिक)

स्वीकृत परियोजनाएं:

दिनांक 01.04.2025 की स्थिति के अनुसार, राजस्थान में पूर्णतः/अंशतः आने वाली 43,918 करोड़ रुपए की लागत वाली कुल 3,409 कि.मी. लंबाई की 28 परियोजनाएँ (13 नई लाइन, 05 आमान परिवर्तन और 10 दोहरीकरण) को स्वीकृत किया गया है। इन कार्यों की स्थिति का सार निम्नानुसार है:-

कोटि	परियोजनाओं की संख्या	कुल लंबाई (कि.मी. में)	कमीशन की लंबाई (कि.मी. में)	व्यय (करोड़ रु. में)
नई लाइन	13	981	196	5769
आमान परिवर्तन	5	1252	788	6829
दोहरीकरण/ बहुपथन	10	1176	254	6357
कुल	28	3,409	1,238	18,954

सभी रेल परियोजनाओं का क्षेत्र-वार/वर्ष-वार ब्यौरा भारतीय रेल की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है।

हाल ही में पूरी की गई परियोजनाएं:

राजस्थान राज्य में पूर्णतः/अंशत: आने वाली हाल ही में पूरी की गईं कुछ परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	नवीनतम लागत (करोड़ रु. में)
1	नीमच-चित्तौड़गढ़ दोहरीकरण (56 किलोमीटर)	560
2	बंगुरग्राम-रास नई लाइन (28 किलोमीटर)	175
3	थईयात हमीरा-सोनू नई लाइन (58 किलोमीटर)	350
4	सूरतपूड़ा-श्रीगंगानगर आमान परिवर्तन (241 किलोमीटर)	896
5	सादुलपुर-बीकानेर एवं रतनगढ़-डेगाना आमान परिवर्तन (438 किलोमीटर)	886
6	जयपुर-चुरू एवं सीकर-लोहारू आमान परिवर्तन (320 किलोमीटर)	1105
7	भगत की कोठी-लूनी दोहरीकरण (28 किलोमीटर)	128
8	रानी-केशव गंज दोहरीकरण (59 किलोमीटर)	290
9	गुड़िया-मारवाड़ एवं करजोदा-पालनपुर दोहरीकरण (49 किलोमीटर)	251
10	रानी-मारवाड़ दोहरीकरण (52 किलोमीटर)	346
11	आबू रोड-स्वरूप गंज दोहरीकरण (26 किलोमीटर)	195
12	आबू रोड-सरोत्रा रोड दोहरीकरण (24 किलोमीटर)	152
13	अलवर-बाँदीकुई दोहरीकरण (60 किलोमीटर)	450
14	अजमेर-बंगुरग्राम दोहरीकरण (48 किलोमीटर)	375
15	बंगुरग्राम-गुड़िया कहीं-कहीं दोहरीकरण (47 किलोमीटर)	395
16	डेगाना-राई का बाग दोहरीकरण (146 किलोमीटर)	809
17	बीना-कोटा दोहरीकरण (282 किलोमीटर)	2476
18	दौसा-गंगापुर सिटी दोहरीकरण (93 किलोमीटर)	950
19	फुलेरा-डेगाना दोहरीकरण (108 किलोमीटर)	702
20	चुरू-रतनगढ़ दोहरीकरण (43 किलोमीटर)	423

जारी परियोजनाएं:

राजस्थान राज्य में पूर्णतः/अंशत: आने वाली शुरू की गई कुछ परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	परियोजना	लागत (करोड़ रु. में)
1	रामगंजमंडी-भोपाल नई लाइन (277 किलोमीटर)	5073
2	पुष्कर-मेड़ता नई लाइन (51 किलोमीटर)	800
3	रींगस-खाटू श्याम जी नई लाइन (17 किलोमीटर)	254
4	तरंगा हिल-आबू रोड नई लाइन (116 किलोमीटर)	2798
5	मेड़ता सिटी-रास नई लाइन एवं मेड़ता रोड स्टेशन पर बाई पास (56 किलोमीटर)	947
6	कोटा विस्तार सहित ग्वालियर-श्योपुर कलां आमान परिवर्तन (284 किलोमीटर)	2913
7	गंगापुर सिटी के लिए विस्तार सहित धौलपुर-सिरमथरा आमान परिवर्तन (145 किलोमीटर)	747
8	मथुरा-झांसी तीसरी लाइन (274 किलोमीटर)	5924
9	आगरा फोर्ट-बांदीकुई दोहरीकरण (150 किलोमीटर)	988
10	सवाई माधोपुर-जयपुर दोहरीकरण (131 किलोमीटर)	1204
11	लूनी-भीलड़ी दोहरीकरण (272 किलोमीटर)	3086
12	चूरू-सादुलपुर दोहरीकरण (58 किलोमीटर)	469
13	सवाईमाधोपुर में बाई पास लाइन (14 किलोमीटर)	304
14	रेवाडी-खाटूवास दोहरीकरण (28 किलोमीटर)	352
15	खाटूवास-नरनौल दोहरीकरण (24 किलोमीटर)	313
16	मारवाड़ में बाई पास लाइन (4 किलोमीटर)	71
17	चुरू में बाईपास लाइन (5 किलोमीटर)	63
18	समदड़ी में बाईपास लाइन (1 किलोमीटर)	26
19	रामदेवरा-पोखरण नई लाइन (13 किलोमीटर)	189
20	लालगढ़-बीकानेर केबिन पूर्व का दोहरीकरण (11 किलोमीटर)	279
21	रींगस-सीकर दोहरीकरण (50 किमी)	470

विगत तीन वर्षों, 2022-23, 2023-24, 2024-25 और चालू वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और उदयपुर जिलों सहित राजस्थान राज्य में पूर्णतः/अंशत: आने वाली 5,666 कि.मी लंबाई के कुल 59 सर्वेक्षणों (25 नई लाइन और 34 दोहरीकरण) को स्वीकृत किया गया है।

किसी भी रेल परियोजना की स्वीकृति कई मानदंडों/कारकों पर निर्भर करती है जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- **प्रत्याशित यातायात अनुमान और प्रस्तावित मार्ग की लाभप्रदता**
- **परियोजना द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली आरंभिक और अंतिम छोर संपर्कता**
- **मिसिंग लिंकों का संयोजन और वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराना**
- **संकुलित/संतृप्त लाइनों का संवर्द्धन**
- **राज्य सरकारों/केन्द्रीय मंत्रालयों, अन्य जन प्रतिनिधियों द्वारा की गई मांगें**
- **रेलवे की अपनी परिचालनिक आवश्यकताओं**
- **सामाजिक-आर्थिक महत्व**
- **निधियों की समग्र उपलब्धता**

रेल परियोजनाओं का पूरा होना विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, जो निम्नानुसार हैं:

- **राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण**
- **वन संबंधी मंजूरी**
- **बाधक जनोपयोगी सेवाओं का स्थानांतरण**
- **विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां**
- **क्षेत्र की भू-वैज्ञानिक और स्थलाकृतिक परिस्थितियां**
- **परियोजना स्थल के क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति**

- परियोजना विशेष के स्थल के लिए किसी वर्ष में कार्य के महीनों की संख्या आदि

ये सभी कारक परियोजना/ओं के समापन समय और लागत को प्रभावित करते हैं।

रेल अवसंरचना परियोजनाएँ क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास को सक्षम बनाती हैं, जिनमें शामिल हैं:

- देश के अन्य भागों के साथ क्षेत्र की बेहतर संपर्कता
- माल और सेवाओं की तेज़ आवाजाही
- संभार तंत्र दक्षता में सुधार
- लाइन क्षमता में बढ़ोतरी
- क्षेत्र की जनता के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर बढ़ाना
- परिचालन संबंधी बाधाओं में कमी
- पर्यटन उद्योग का विकास और क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि

****